[2024] 10 एस.सी.आर. 1313 : 2024 आईएनएससी 755

रमा देवी

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

(2014 का आपराधिक अपील सं.(ओं) 2623-2631)

03 अक्टूबर 2024

[संजीव खन्ना,* संजय कुमार और आर. महादेवन, न्यायमूर्ति]

विचारा के लिए मुद्दा

क्या उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय को पलटना और दंड संहिता, 1860 की धारा 34 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 27 के साथ पठित धारा 302,307,333,355 और 379 के तहत दंडनीय आरोपों से उत्तरवादियों को दोषमुक्त करना न्यायोचित था।

हेडनॉट्स

दंड संहिता, 1860-धारा 302, 307, धारा 34 के साथ पठित – एक विधायक और उसके अंगरक्षक की हत्या- प्रतिवादीओं को विचारण न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया -उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को पलट दिया गया-चुनौती दी गयी।

अभिनिर्धारित: अभिलेख पर साक्ष्य और सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए, ए-4 और ए-8 के खिलाफ धारा 307 और धारा 307 के साथ पठित धारा 34 के तहत आरोप साबित और उचित संदेह से परे स्थापित हुए-विचारण न्यायालय द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की गई और बहाल की गई-हालाँकि, अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को संदेह का लाभ दिया गया क्योंकि उनकी संलिप्तता वाला कोई प्रत्यक्ष चक्षु-साक्ष्य नहीं है और षड्यंत्र के आरोप की पुष्टि

नहीं की गई है, उनके दोषमुक्ति को बरकरार रखा गया-आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है। [पैरा 42-45]

प्रथमिकी -प्रतिलिपि को दंडाधिकारी को भेजने में विलंब -जब घातक न होः

अभिनिर्धारितः यह घटना दिनांक 13.06.1998-14.06.1998 रविवार की रात्रि को होने के कारण,प्रथम सूचना प्रतिवेदन दिनांक 15.06.1998 को क्षेत्राधिकार वाले दंडाधिकारी को भेजा गया। इस प्रकार,क्षेत्राधिकार वाले दंडाधिकारी को भेजने में विलंब को स्पष्ट किया गया-केवल विलंब अपने आप में अभियोजन पक्ष के मामले को ख़ारिज करने और उस पर विश्वास न करने के लिए पर्याप्त नहीं है,जब तक की अभियुक्त यह प्रदर्शित न करदे कि इस विलंब ने उनके मामले को किस प्रकार प्रभावित किया है। यदि अन्वेषण सही तरीके से शुरू होता है और अभिलेख पर यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि अभियुक्तों का नाम लिया गया था और उन्हें चिन्हित किया गया था, तो अभियोजन पक्ष का मामला तभी स्वीकार किया जा सकता है जब साक्ष्य अभियुक्त को दोषी ठहराते हों - अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट को प्राथमिकी की एक प्रति भेजने और प्राप्त करने की आवश्यकता पूर्व तिथि या पूर्व समय की प्राथमिकी के खिलाफ एक बाहरी नियंत्रण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राथमिकी में कोई हेरफेर या छेड़छाड़ नहीं है - इसके अलावा, अगर अदालत गवाहों को सच्चा और विश्वसनीय पाती है, तो देरी के लिए एक ठोस स्पष्टीकरण की कमी को हानिकारक नहीं माना जा सकता है। [पैरा 30]

साक्ष्य- अपराध में उपयोग किए गए वाहनों और हथियारों की गैर-प्राप्ति -प्रत्यक्षदर्शियों की विश्वसनीयता पर प्रभाव, यदि कोई हो तोः

अभिनिर्धारितः गवाहों के मौखिक संस्करण की केवल इसलिए अवहेलना नहीं की जानी चाहिए क्योंकि अपराध में इस्तेमाल किया गया हथियार और अभियुक्त द्वारा अभिकथित रूप से उपयोग किए गए वाहन पुलिस द्वारा खोजे या जब्त नहीं किए गए थे-तथ्यों के आधार पर, वाहनों और हथियारों को बरामद करने में पुलिस की विफलता प्रत्यक्षदर्शी विवरणों की

विश्वसनीयता या दोनों मृतक की हत्या के कारण के बारे में पुष्टि करने वाले साक्ष्य को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं है। [पैरा 27]

साक्ष्य- आपराधिक पृष्ठभूमि वाले गवाह-न्यायालय सावधानी बरतें, लेकिन साक्ष्य को केवल आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता हैः

अभिनिर्धारितः एक गवाह की आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए आवश्यक है कि न्यायालय सावधानी के साथ अपने साक्ष्य का उपयोग करें-एक विवादास्पद अतीत वाले गवाह की गवाही को मामले के आसपास के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किए बिना असत्य या अविश्वसनीय के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है, जिसमें अपराध स्थल पर उनकी उपस्थिति भी शामिल है-प्रतिद्वंद्वी गिरोहों या समूहों के बीच संघर्ष वाले मामलों में, दोनों पक्षों के सदस्यों की गवाही स्वीकार्य और प्रासंगिक है-यदि न्यायालय ऐसी गवाही की सत्यता और सच्चाई के बारे में आश्वस्त है, तो इस पर विचार किया जा सकता है-न्यायालय यह निर्धारित करने के लिए व्यापक संदर्भ का आकलन करती हैं कि क्या पर्याप्त पुष्टि है, जब तक कि साक्ष्यो को झूठा साबित करने का कोई वैध कारण नहीं हैं-महत्वपूर्ण परीक्षण यह है कि क्या गवाह वास्तव में एक प्रत्यक्षदर्शी है और क्या उनकी गवाही विश्वसनीय है - यदि घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति संदेह से परे स्थापित हो जाती है, तो घटना के उनके विवरणों पर भरोसा किया जा सकता है-ऐसे साक्ष्य को केवल आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। [पैरा 20]

साक्ष्य - घटनास्थल (अस्पताल) में प्रत्यक्षदर्शी (अ. सा. -1) की उपस्थिति सिद्ध हुई, हालांकि अस्पताल और कारागृह नयाचार का पालन नहीं किया गया - अ. सा. -1 की गवाही पर भरोसा, यदि उचित हो - विधायक और उनके अंगरक्षक की हत्या उस अस्पताल में की गई जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था - अ. सा. -1 ने अदालत या जेल अधिकारियों से पूर्व अनुमति नहीं ली और न ही अस्पताल में मृतक विधायक से मिलने के दौरान अस्पताल के रजिस्टर में कोई प्रविष्टि की:

अभिनिर्धारित किया: फर्दबयान (प्रदर्श-50) और पी.डब्लू.-24 और पी.डब्लू.25 के प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य अस्पताल में पी.डब्लू.-1 और अन्य आगंतुकों की उपस्थिति स्थापित करते हैं - एक बार जब घटनास्थल पर गवाह की उपस्थिति साबित हो जाती है, तो उनकी गवाही, यदि विश्वसनीय और सत्य है, तो उसे केवल अस्पताल और कारागृह नयाचार का पालन न करने के आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए - इसके अलावा, पी.डब्लू.-1 के प्रत्यक्षदर्शी बयान को नजरअंदाज करने और संदेह करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क, इस आधार पर कि उसे सुचक होना चाहिए था क्योंकि वह मृतक विधायक का साला है और घटना के समय अस्पताल में मौजूद था, अनुमानात्मक और निराधार है - कोई भी व्यक्ति किसी मामले का सुचक हो सकता है, और पुलिस भी अपने दम पर मामला दर्ज कर सकती है - पी.डब्लू.-1 की गवाही को खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय का तर्क मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। [पैरा 15]

साक्ष्य-पक्षद्रोही साक्षी की गवाही-सूक्तियां-फाल्सस इन यूनो ,फाल्सस इन ओम्निबस-अनुपयुक्तता:

निर्णय: इस देश की परिस्थितियों में फाल्सस इन यूनो, फाल्सस इन ओम्नीबस का सिद्धांत लागू करने के लिए उचित नियम नहीं है - यह सिद्धांत कानून के शासन का दर्जा नहीं रखता - यह केवल सावधानी का नियम है, जिसमें साक्ष्य के वजन का प्रश्न शामिल है जिसे न्यायालय दिए गए परिस्थितियों में लागू कर सकता है - किसी पक्षद्रोही गवाह के साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जाना चाहिए, ताकि अभियोजन पक्ष का समर्थन करने वाले संस्करणों को बाहर रखा जा सके - बल्कि, पक्षद्रोही गवाह की गवाही की बारीकी से जांच की जानी चाहिए, ताकि न्यायालय सत्य को झूठ, अतिशयोक्ति और सुधारों से अलग कर सके - केवल विश्वसनीय साक्ष्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए - न्यायालय को उचित मूल्यांकन करने की अपनी शक्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए - किसी पक्षद्रोही गवाह की पूरी गवाही को केवल तभी खारिज किया जाता है जब न्यायाधीश विवेक के आधार पर गवाह को

पूरी तरह से अविश्वसनीय पाता है, जिससे साक्ष्य को पूरी तरह से बाहर रखा जा सकता है - साक्ष्य के विश्वसनीय हिस्से मामले में साक्ष्य के उद्देश्य से गवाही पर विचार किया जाना चाहिए। [पैरा 16, 22]

न्याय दृष्टान्त

दीप चंद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य **(1969) 3 एस.सी.सी. 890;** राजस्थान राज्य बनाम दाऊद खान **(2016) 2 एस.सी.सी. 607;** पोन्नम चंद्रैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2008) 11 एस.सी.आर. 561**:(2008) 11 एस.सी.सी. 640;** यू. पी. राज्य बनामफरीद खान और अन्य **(2005) 9 एस.सी.सी. 103;** सी. मुनियप्पन और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य [2010] 10 एससीआर 262**:(2010) 9 एस.सी.सी. 567;** योगेश सिंह बनाम महाबीर सिंह और अन्य [2016] 7 एससीआर 713**:(2017) 11 एस.सी.सी. 195;** राजस्थान राज्य बनाम अर्जुन सिंह और अन्य (2011) 10 एससीआर 823**:(2011) 9 एस.सी.सी. 115-पर निर्भर था।**

अधिनियमों की सूची

दंड संहिता, 1860; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; शस्त्र अधिनियम, 1959

मुख्य शब्दों की सूची

हत्या; विधानसभा सदस्य; विधायक; अंगरक्षक; राजनीतिक नेता; संदेह का लाभ; दोषमुक्त; षड्यंत्र सिद्ध/प्रमाणित नहीं; उद्देश्य; आरोप उचित संदेह से परे सिद्ध हुए; अस्पताल; कारागृह नयाचार; अस्पताल पंजिका; आगंतुक; दंडाधिकारी को प्रथमिकी अग्रेषित करने में विलंब; घातक नहीं; पूर्व दिनांकित; पूर्व समयबद्ध; प्रथमिकी में छलसाधन या हस्तक्षेप; बाह्य मुद्दे; स्मृति परीक्षण; आपराधिक पृष्ठभूमि के साथ गवाह; वाहनों की गैर-पुनर्प्राप्ति, अपराध में

उपयोग किए गए हथियार; चक्षु साक्ष्य; सूचनादाता; पक्षद्रोही साक्षी; सूक्ति; फाल्सस इन यूनो, फाल्सस इन ओम्निबस; फर्दबयान; प्रत्यक्षदर्शी; समय की समाप्ति।

प्रकरण से उत्पन्न

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2014 का आपराधिक अपील संख्या 2623-2631

2009 के सी.आर.एल.ए.पी. सं. 778,898,825,859,865,899,871,874 और 878 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 24.07.2014 के निर्णय एवं आदेश से

2014 के आपराधिक अपील संख्या 2632-2640 के साथ

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

तुषार मेहता, महा सॉलिसिटर, के. एम. नटराज, ए. एस. जी., सिद्धार्थ अग्रवाल, सुश्री सोनिया माथुर, श्रीमती रुचि कोहली, श्रीमती अर्चना पाठक दवे, सुरेंद्र सिंह, वरीय अधिवक्तागण, अरविंद कुमार शर्मा, आदित्य सिंगिया, विश्वजीत भाटी, हर्ष यादव, ऋत्विक साहा, शरद कुमार पुरी, सुश्री पारुल शर्मा, श्रीमती पिंकी अग्रवाल, श्रीमती प्रिया पुरी, मुकेश कुमार मरोरिया, सुश्री साइरिका एस राजू, राजेश कुमार सिंह, राजन कुमार चौरसिया, पी. वी. योगेश्वरन, सुश्री रोनिका टेटर, सुश्री सुरभी भारद्वाज, सुश्री दीपांशु कृष्णन, सुश्री मधुमिता केशवन, निखिल चंद्र जैसवाल, त्रिपुरारी रे, डी. एस. परमार, सुश्री सुजीता श्रीवास्तव, अभिषेक प्रियदर्शी, सुश्री मृणाल एल्कर मजूमदार, सौरभ सिंह, अनिरुद्ध रे, आशुतोष घाड़े, सुनील कुमार, निमित भीमजियानी, राहुल रमन, सुश्री स्नेहा बालापुरे, राज कमल, असीम अटवाल, कर्तव्य बत्रा, अनुराग चंद्र, सुश्री नूपुर कौशिक, सुश्री स्तुति, सुश्री अपराजित त्यागी, सुश्री मुस्कान सिदाना, हरनीत सिंह, सुश्री प्रेरणा सिंह, शांतनु सागर, राज कुमार, प्रभात रंजन राज, अनिल कुमार, गुंजेश रंजन, श्रीमती दिव्या मिश्रा, शशांक कुमार सौरव, संजय जैन, मनु शंकर मिश्रा, लक्ष्मी नारायण शर्मा, विवेकानंद सिंह, निशांत कुमार, नित्यानंद मूर्ति पी, सुश्री भानु प्रभा, वैभा कुमार, अधिवक्तागण उपस्थित पक्षों के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति

यह निर्णय दो तरह के अपीलों का निर्धारण करता है, एक बिहार राज्य द्वारा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो[1] के माध्यम से, और मृतक में से एक बृज बिहारी प्रसाद एक बिहार विधान सभा के सदस्य की पत्नी रमा देवी द्वारा। दूसरा मृतक - लक्ष्मेश्वर साहू-बृज बिहारी प्रसाद के अंगरक्षक और बिहार पुलिस के सदस्य थे।

2. पटना उच्च न्यायालय में दिनांक 24.07.2014 के आक्षेपित निर्णय के द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय को पलट देता है और नौ[2] अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता[3], 1860 की धारा 34, और शस्त्र अधिनियम, 1959[4] की धारा 27' के साथ पठित धारा 307,333,355 और 379 के तहत दंडनीय आरोपों में से दोषमुक्त कर देता है।

3. प्रश्नगत घटना दिनांक 13.06.1998 को लगभग 08:15 बजे इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना[5] में घटित हुई थी। 5 एसएसपी यादव, निरीक्षक-सह-प्रभारी पदाधिकारी, शास्त्री नगर थाना[6] द्वारा दिनांक 13.06.1998 को रात्रि 9:00 बजे दर्ज अमरेन्द्र कुमार सिन्हा (अ. सा. -10) के फर्दबयान (प्रदर्श 50) के आधार पर दिनांक 14.06.1998 को 12:15 बजे पूर्वाह्न में भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 34,

1 संक्षेप में 'सी.बी.आई'

2 सूरज भान सिंह उर्फ सूरज सिंह उर्फ सूरज, मुकेश सिंह, ललन सिंह, मंटू तिवारी, कैप्टन सुनील सिंह (अब मृत), राम निरंजन चौधरी, शशि कुमार राय (अब मृत), विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी।

3 संक्षेप में, "दं.प्र.सं."

4 संक्षेप में, "1959 अधिनियम"

5 संक्षेप में, "आईजीआईएमस अस्पताल"

6 एस.एस.पी. यादव की बाद में मृत्यु हो गई और उन्होंने गवाही नहीं दी।

120बी, 379 तथा 1959 अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट[7] संख्या 336/1998 (प्रदर्श 51 एवं 51/1) दर्ज की गई थी।

<u>अभियोजन पक्ष का मामला</u>

4. अभियोजन पक्ष का मामला इस प्रकार हैः

(i) 13.06.1998 को शाम करीब 6:30 बजे न्यायिक हिरासत में चल रहे और आईजीआईएमएस अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती बृज बिहारी प्रसाद वार्डरूम के बाहर टहल रहे थे। उनके साथ अमरेंद्र कुमार सिन्हा (अ.सा. -10), अरबिंद सिंह (अ.सा. -13), राम नंदन सिंह (अ.सा. -12), महंत अश्वनी दास (अ. सा. -25), पारस नाथ चौधरी (अ.सा. -1), ओंकार सिंह और 2-4 अन्य लोग थे।

(ii) बृज बिहारी प्रसाद के साथ उनके अंगरक्षक लक्ष्मेश्वर साहू भी थे, जो कार्बाइन से लैस थे और अन्य सिपाही भी थे।

(iii) दो वाहन, एक सूमो कार, जिसका पंजीकरण संख्या बीआर-1पी-1818 है, उसके पीछे एक एंबेसडर कार, जिसका पंजीकरण संख्या पता नहीं चल सका, बेली रोड की ओर से आईजीआईएमएस अस्पताल में प्रवेश किया और बृज बिहारी प्रसाद के पास रुक गया।

(iv) उक्त कारों में सवार लोग, अर्थात् - मंटू तिवारी (ए-4), विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला (ए-8), राजन तिवारी (ए-9), और श्री प्रकाश शुक्ला उर्फ शिव प्रकाश शुक्ला (अब मृत), सतीश पांडे (अब मृत) और भूपेंद्र नाथ दुबे (अब मृत) वाहनों से बाहर निकले।

(v) मंटू तिवारी (A-4) एक स्टेन गन से लैस था और अन्य सभी पिस्तौल से लैस थे। भूपेंद्र नाथ दुबे (अब मृत) ने दूसरों को बृज बिहारी प्रसाद पर गोली चलाने

7 संक्षेप में, "एफ. आई. आर".।

के लिए उकसाया, जबकि उसने खुद भी अपनी पिस्तौल से बृज बिहारी प्रसाद पर गोली चलाई।

(vi) मंटू तिवारी (ए-4) और श्री प्रकाश शुक्ला उर्फ शिव प्रकाश शुक्ला (अब मृत) ने क्रमशः अपनी स्टेन गन और पिस्तौल से बृज बिहारी प्रसाद पर गोली चलाई।

(vii) सतीश पांडे, विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला (ए-8) और राजन तिवारी (ए-9) ने लक्ष्मेश्वर साहू पर गोली चलाई।

(viii) बृज बिहारी प्रसाद और लक्ष्मेश्वर साहू दोनों बेहोश हो गए और उनकी मौत हो गई।

(ix) रवींद्र भगत (अ. सा. -14) को क्रॉस-फायर में गोली लगी।

5. दिनांक 14.06.1998 की पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श 9 और 9/1), जिसे डॉ. अरविंद कुमार सिंह (अ. सा. -7) द्वारा सिद्ध किया गया है, बृज बिहारी प्रसाद और लक्ष्मेश्वर साहू की हत्या कई गोलियों के कारण हुई जख्मों के कारण हुई, जिसके परिणामस्वरूप रक्तस्राव और सदमे की स्थिति पैदा हुई। कई गोलियों के घाव की प्रविष्टियाँ आग्नेयास्त्रों/पिस्तौल से लगातार गोलीबारी के अनुरूप हैं। इस हद तक अभियोजन पक्ष का कथन निर्विवाद है।

6. अभियोजन पक्ष के अनुसार, ग्यारह चश्मदीद गवाह थे, अर्थात्, पारस नाथ चौधरी (अ.सा. -1), अमरेंद्र कुमार सिन्हा (अ.सा. -10), आमोद कुमार (अ.सा. -11), राम नंदन सिंह (अ.सा. -12), अरबिंद सिंह (अ.सा. -13), रवीन्द्र भगत (अ.सा. -14), कामाख्या नारायण सिंह (अ.सा. -15), भोला प्रसाद प्रेमी (अ.सा. -16), महंथ अश्वनी दास (अ.सा. -25), शशि भूषण सिंह (अ.सा. -42) और बिनोद कुमार सिंह (अ.सा. -19). हालाँकि, पारस नाथ चौधरी (अ.सा. -1), महंत अश्वनी दास (अ.सा. -25), शशि

अन्य लोग प्रतिकूल या आंशिक रूप से प्रतिकूल थे क्योंकि उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया या अपराधियों का नाम/पहचान नहीं की।

7. मुख्य रूप से पारस नाथ चौधरी (अ. सा. -1), महंत अश्विनी दास (अ. सा. -25), शशि भूषण सिंह (अ. सा. -42) और अमरेंद्र कुमार सिन्हा (अ. सा. -10) की गवाही पर भरोसा करते हुए, विचरण न्यायालय ने उत्तरवादियों सूरज भान सिंह (ए-1), मुकेश सिंह (ए-2), लल्लन सिंह (ए-3), मंटू तिवारी (ए-4), कैप्टन सुनील सिंह (ए-5) (अब मृत)[8], 8 राम निरंजन चौधरी (ए-6), विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला (ए-8), राजन तिवारी (ए-9) और शशि कुमार राय (ए-7) (अब मृत)[9] को दोषी ठहराया

<u>उच्च न्यायालय का तर्क</u>

8. उच्च न्यायालय के निर्णय में साक्ष्यों का विस्तार से उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रतिवादियों को बरी करने का आधार निम्नलिखित निष्कर्ष हैं:

(i) एफआईआर संख्या 336/1998, जिस पर प्रदर्श 51 अंकित है, समय से पहले की है।

(ii) शशि भूषण सिंह (अ.सा.-42) प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, बल्कि एक प्लांटेड गवाह है, क्योंकि उसका नाम फर्दबयान (प्रदर्श 50) में नहीं लिखा गया है। उसका पिछला इतिहास संदिग्ध है।

(iii) प्रतिवादी-आरोपी को फंसाने वाली पारस नाथ चौधरी (अ. सा.-1) की गवाही अविश्वसनीय है क्योंकि:

(क) वह बृज बिहारी प्रसाद का साला है;

8 यह एक स्वीकृत और मान्य स्थिति है कि कैप्टन सुनील सिंह (ए-5) का निधन हो गया है। उनके विरुद्ध अपील निरस्त मानी जाएगी।

9 शशि कुमारी राय (ए-7) के विरुद्ध अपील उनकी मृत्यु के कारण दिनांक 28.02.2020 के आदेश के अनुसार निरस्त कर दी गई।

(ख) उसे सुचक होना चाहिए था, लेकिन वह नहीं था, जिससे आईजीआईएमएस अस्पताल में उसकी उपस्थिति पर संदेह पैदा होता है;

(ग) उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का खंडन करते हुए स्वीकार किया कि राजन तिवारी (ए-9), जिसे वे पहले से जानते थे, घटना के दौरान मौजूद नहीं थे। हालांकि, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973[10], की धारा 161 के तहत अपने बयान में उन्होंने दावा किया कि राजन तिवारी (ए-9) लक्ष्मेश्वर साहू के हमलावरों में से एक थे; और

(घ) उन्होंने अपनी बहन रमा देवी (अ.सा.-24) के दबाव में गवाही दी, जो सभी (तीनों) दिनों में उनके साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के दौरान अदालत में मौजूद थीं।

(iv) महंथ अश्विनी दास (अ.सा.-25) की गवाही निम्नलिखित आधारों पर अविश्वसनीय है:

(क) वह वर्ष 1979 में दर्ज एक हत्या के मामले में दोषी है;

(ख) उसने उच्च न्यायालय द्वारा उसकी अपील खारिज होने के बाद आत्मसमर्पण नहीं किया और तदनुसार उसे फरार घोषित कर दिया गया;

(ग) उसे वर्तमान मामले में विचरण न्यायालय के समक्ष गवाही देते समय 04.05.2006 को गिरफ्तार किया गया था;

(घ) वह बृज बिहारी प्रसाद और उनकी पत्नी रमा देवी (अ. सा.-24) के संरक्षण में था;

10 संक्षेप में, "दं.प्र.सं."।

(ङ) आईजीआईएमएस अस्पताल में बृज बिहारी प्रसाद के अस्पताल कक्ष में उनकी उपस्थिति के बारे में शशि भूषण सिंह (अ.सा.-42) और महंथ अश्विनी दास (अ.सा.-25) के बयानों में विरोधाभास है। जबकि शशि भूषण सिंह (अ.सा.-42) का दावा है कि महंथ अश्विनी दास (अ.सा.-25) जब वहां पहुंचे तो अस्पताल कक्ष में थे, महंथ अश्विनी दास (अ.सा.-25) का कहना है कि शशि भूषण सिंह (अ.सा.-42) पहले से ही बृज बिहारी प्रसाद के अस्पताल कक्ष में मौजूद थे जब वह (महंथ अश्विनी दास) अस्पताल पहुंचे।

(च) इस बात में विसंगति है कि पुलिस ने 13.06.1998 और 14.06.1998 को महंथ अश्वनी दास (अ.सा.-25) का बयान कब दर्ज किया और घटनाओं के बारे में उनका बयान कब दर्ज किया। महंथ अश्वनी दास (अ.सा.-25) का दावा है कि घटना के बाद वह और रमा देवी (अ.सा.-24) लगभग 9:00-9:30 बजे आईजीआईएमएस अस्पताल से बृज बिहारी प्रसाद के सरकारी आवास पर गए थे। महंथ अश्वनी दास (अ.सा.-25) 14.06.1998 को लगभग 12:30 बजे रात में मुजफ्फरपुर मठ के लिए निकल गए थे। इस प्रकार, पुलिस 14.06.1998 को 12:30 बजे आईजीआईएमएस अस्पताल में महंथ अश्वनी दास (अ. सा.-25) का बयान दर्ज नहीं कर सकती थी। इसके अलावा, यदि महंत अश्विनी दास (अ. सा.-25) घटना के समय मौजूद थे, जैसा कि उन्होंने बयान दिया है, तो पुलिस को उनके आईजीआईएमएस अस्पताल परिसर से रात 9:30 बजे के आसपास निकलने से पहले उनका बयान दर्ज करना चाहिए था।

(v) शशि भूषण सिंह (अ.सा.-42) प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे, क्योंकि उनकी उपस्थिति फर्दबयान (प्रदर्श 50) या एफआईआर (प्रदर्श 51 और 51/1) में दर्ज नहीं है। दं. प्र. सं. की धारा 161 के तहत उनका बयान घटना के पांच दिन बाद देरी से दर्ज किया गया था।

(vi) रमा देवी (अ.सा.-24) प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं, क्योंकि वह घटना से पहले घटनास्थल से चली गई थीं। पुलिस ने दं. प्र. सं. की धारा 161 के तहत रमा देवी का बयान पेश नहीं किया, जो 13.06.1998 को दूसरे जांच अधिकारी[11] शशि भूषण शर्मा (अ.सा.-54) द्वारा दर्ज किया गया था, जिन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना के निर्देशों के अनुपालन में जांच का प्रभार संभाला था। रमा देवी (अ.सा.-24) का यह कथन कि उसने हमलावरों के नाम और विवरण अस्पताल के कमरे में दिन में पहले मिले आगंतुकों से जाना, उसका उल्लेख दं. प्र. सं. की धारा 161 के तहत दिनांक 18.10.1999 और 28.03.2001 को उसके द्वारा सीबीआई के आईओ राय सिंह खत्री (अ. सा.-62) को दिए गए बयानों में नहीं है। इसकी पुष्टि सीबीआई के आईओ राय सिंह खत्री (अ.सा.-62) के बयान से होती है, जिन्होंने गवाही दी कि रमा देवी (अ.सा.-24) ने हमलावरों का नाम नहीं बताया। चूंकि शशि भूषण शर्मा (अ.सा.-54) द्वारा धारा 161 दं.प्र.सं. के तहत दर्ज रमा देवी (अ.सा.-24) का प्रारंभिक बयान रिकॉर्ड पर नहीं था और बाद में वह सीबीआई के आईओ राय सिंह खत्री (अ.सा.-62) को धारा 161 दं.प्र.सं. के बयानों में हमलावरों के नाम का खुलासा करने में विफल रही, इसलिए अदालत में उसके बयान में कहा गया है कि पारस नाथ चौधरी (अ.सा.-1), राम निरंजन चौधरी (ए-6), कामाख्या नारायण सिंह (अ.सा.-15), अरबिंद सिंह (अ.सा.-13), अमरेंद्र कुमार सिन्हा

11 संक्षेप में, "आईओ"।

(सूचनाकर्ता/अ.सा.-10), ओंकार सिंह, महंथ अश्वनी दास (अ.सा.-25), शशि भूषण सिंह (अ. सा.-42) और अन्य मृतक के साथ मौजूद थे, इसलिए इस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए।

(vii) प्रत्यक्षदर्शियों ने घटनास्थल पर मौजूद बृज बिहारी प्रसाद के सुरक्षाकर्मियों द्वारा जवाबी फायरिंग के बारे में कोई गवाही नहीं दी। खाली कारतूसों की बरामदगी और आग्नेयास्त्र परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श-17) से पता चलता है कि सुरक्षाकर्मियों को दी गई चार राइफलों में से दो से गोलियां चलाई गई थीं।

न्यायालय में बयान और साक्ष्य का विश्लेषण

9. हम अब उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों की जांच करने से पहले पारस नाथ चौधरी (अ. सा. -1),महंत अश्विनी दास (अ. सा. -25), अमरेंद्र कुमार सिंह (अ. सा. -10) और रमा देवी (अ. सा. -24) के न्यायालय में बयान की कुछ विस्तार से जांच करेंगे। हमारी चर्चा दोनों पक्षों द्वारा उठाई गई दलीलों को भी संबोधित करेगी, विशेष रूप से उत्तरवादियों के इस तर्क पर ध्यान केंद्रित करेगी कि पारस नाथ चौधरी (अ. सा. -1), महंत अश्विनी दास (अ. सा. -25), अमरेंद्र कुमार सिंह (अ. सा. -10) और रमा देवी (अ. सा. -24) के न्यायालय में बयान को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

10. सर्वप्रथम, हम शशि भूषण [अ. सा. 42]की घटना स्थल पर उपस्थिति और परिणामस्वरूप, निम्नलिखित कारणों से एक चश्मदीद गवाह के रूप में उनकी गवाही पर अविश्वास करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क के साथ अपनी सहमति व्यक्त करते हैं:

(i) शशि भूषण सिंह (अ. सा. -42) का उल्लेख फर्दबयान (प्रदर्श-50) में घटना स्थल पर उपस्थित व्यक्तियों में से एक के रूप में नहीं किया गया है, और साथ ही प्राथमिकी (प्रदर्श 51 और 51/1) में भी नहीं किया गया है। इन

दस्तावेजों में प्रत्यक्षदर्शियों के नाम हैं। इसलिए, शशि भूषण सिंह (अ. सा. -42) के नाम की अनुपस्थिति महत्वपूर्ण है।

(ii) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत उनका बयान 18.06.1998 को दर्ज किया गया था, अर्थात घटना की तिथि के 5 दिन बाद;

(iii) शशि भूषण सिंह (अ. सा. -42) ने बृज बिहारी प्रसाद के शव को पटना से बृज बिहारी प्रसाद के पैतृक स्थान बेहहारी गांव ले जाने के बारे में बयान दिया है। इसलिए, उनके धारा 161 सी. आर.पी.सी. बयान में विलंब से उनके प्रत्यक्षदर्शी होने के दावे को नुकसान पहुंचता है, जिससे यह स्वीकार करने के योग्य नहीं है;

(iv) हालांकि पारस नाथ चौधरी (पी. डब्ल्यू.-1), महंत अश्विनी दास (पी. डब्ल्यू.-25), और रमा देवी (पी. डब्ल्यू.-24) ने चश्मदीद गवाह के रूप में शशि भूषण सिंह (पी. डब्ल्यू.-42) की उपस्थिति की गवाही दी है, इस दावे को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। फर्दबयान (प्रदर्श-50), घटना के तुरंत बाद बनाया गया पहला लिखित विवरण है, जो विवाद रहित है। इसके अलावा, एक प्रत्यक्षदर्शी के रूप में शशि भूषण सिंह (अ. सा. -42) का बयान दर्ज करने में पांच दिनों की अस्पष्ट विलंब उनके विवरणों की विश्वसनीयता को कम करती है।

(v) इसी कारण से अभियोजन पक्ष द्वारा अमरेन्द्र कुमार सिन्हा (अ. सा.-10) की अदालती गवाही पर भरोसा करना, जिसमें शशि भूषण सिंह (अ. सा.-42) की घटनास्थल पर मौजूदगी का दावा किया गया है, उनके फर्दबयान के विपरीत, अनिश्चित और अविश्वसनीय है। अमरेन्द्र कुमार सिन्हा (अ. सा.-10) ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया, फिर भी इस तथ्य के प्रति सचेत होने के बावजूद कि वह फर्दबयान के सुचक थे, वह पूरी

तरह से मुकर नहीं सके। शशि भूषण सिंह (अ.सा.-42) की मौजूदगी के बारे में उनके बयान पर सही रूप से अविश्वास किया गया है।

<u>पारस नाथ चौधरी की गवाही (अ.सा.-1)</u>

11. पारस नाथ चौधरी (अ.सा. -1) 13.06.1998 को लगभग 6:40–7:00 बजे पूर्वाह्न में बृज बिहारी प्रसाद से मिलने के लिए अस्पताल में अपनी उपस्थिति के बारे में स्पष्ट हैं। उन्होंने उन व्यक्तियों के नाम बताए जो अस्पताल कक्ष में उनके साथ उपस्थित थे, जिसमें महंत अश्विनी दास (अ.सा. -25) शामिल हैं। गवाही में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

(i) बृज बिहारी प्रसाद अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों और उनसे मिलने आए समर्थकों के साथ टहलने गए। उनकी सुरक्षा के लिए नियुक्त पुलिसकर्मी भी उनके साथ थे।

(ii) कुछ समय बाद, दो वाहन-एक सफेद सूमो कार (पंजीकरण संख्या बी.आर.-1पी.-1818) और एक सफेद एम्बेसेडर कार अस्पताल में आई और बृज बिहारी प्रसाद के सामने लगभग 20 कदमों की दूरी पर रुकी।

(iii) भूपेंद्र नाथ दुबे (मृत) सुमो कार से उतरे, जिसमें 2-3 और लोग भी सवार थे। 2-3 अन्य लोग भी एम्बेसडर कार से उतरे।

(iv) भूपेंद्र नाथ दुबे (मृत) ने बृज बिहारी प्रसाद की ओर इशारा किया और उन्हें मारने का आदेश दिया, जबकि उन्होंने खुद भी गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलीबारी में अन्य लोग भी उनके साथ शामिल हो गए।

(v) पारस नाथ चौधरी (अ.सा.-1) ने विशेष रूप से सतीश पांडे (अब मृत) की पहचान एम्बेसडर कार के सवार के रूप में की।

(vi) विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला (ए-8), जो लाल गंज से विधायक थे, एम्बेसेडर कार से उतरे, जबकि मंटू तिवारी (ए-4), 1-2 और लोगों के साथ, सूमो से उतरे।

(vii) पारस नाथ चौधरी (अ.सा. -1) ने मंटू तिवारी (ए-4) को देखा था लेकिन उनका नाम नहीं जानते थे। उन्हें बाद में अमरेंद्र कुमार सिन्हा (अ.सा. -10) और शशि भूषण सिंह (अ.सा. -42) से नाम के बारे में पता चला।

(viii) मंटू तिवारी (ए-4) के पास एक बड़ी बन्दूक थी जबकि भूपेंद्र नाथ दुबे (अब मृतक) के पास एक छोटी बन्दूक थी। अन्य हमलावरों के पास या तो एक रिवाल्वर या एक छोटी बंदूक थी।

(ix) अंगरक्षक लक्ष्मेश्वर साहू, जो एक कार्बाइन ले जा रहे थे, पर भी गोली चलाई गई।

(x) गोलीबारी के परिणामस्वरूप, लक्ष्मेश्वर साहू और बृज बिहारी प्रसाद दोनों गिर गए।

(xi) जाते समय, भूपेंद्र नाथ दुबे (अब मृत) ने लक्ष्मेश्वर साहू की कार्बाइन ली और "*जय बजरंग बली*" का नारा लगाया।

(xii) हमलावरों के जाने के बाद, पारस नाथ चौधरी (अ.सा. -1) और अन्य आगंतुक बृज बिहारी प्रसाद और लक्ष्मेश्वर साहू के मृत शरीर के पास गए।

(xiii) पारस नाथ चौधरी (अ.सा. -1) ने न्यायालय में मंटू तिवारी (ए-4) और विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला (ए-8) दोनों की पहचान की।

(xiv) जबकि पारस नाथ चौधरी (अ.सा. -1) ने न्यायालय में राजन तिवारी (ए-9) की पहचान की, उसने गवाही दी कि राजन तिवारी (ए-9) घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था। पारस नाथ चौधरी (अ.सा. -1) ने सूरज भान सिंह (ए-1) और शशि कुमार राय (ए-7) को घटना स्थल पर नहीं देखा था।

(xv) पारस नाथ चौधरी (अ.सा. -1) अमरेंद्र कुमार सिन्हा (अ. सा. -10), अरबिंद सिंह (अ.सा. -13), शशि भूषण सिंह (अ. सा. -42), राम नंदन सिंह (अ.सा. -12), महांत अश्विनी दास (अ.सा. -25), रवींद्र भगत (अ.सा. -14), जमुई निवासी कांति, कामाख्या नारायण सिंह (अ.सा. -15), राम निरंजन चौधरी (ए-6), विजय झा (अ.सा. -51) और 2-3 अन्य लोगों की उपस्थिति को आइ.जी.आइ.एम.एस अस्पताल में स्थापित करता है।

12. पारस नाथ चौधरी (अ.सा. -1) का प्रति-परीक्षण निम्नलिखित पहलुओं को प्रकाश में लाती हैः

(i) उन्होंने स्वीकार किया कि रमा देवी (अ.सा. -24) उनकी बहन थीं और वह सुनवाई के दिन न्यायालय में उपस्थित थीं, लेकिन उनके साक्ष्य दर्ज किए जाने के दौरान वह चली गईं।

(ii) उन्होंने पुष्टि की कि बृज बिहारी प्रसाद को घटना से 10-12 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

(iii) घटना की तिथि से पहले, वे बृज बिहारी प्रसाद से 4-5 अवसरों पर अस्पताल में मिले।

(iv) बृज बिहारी प्रसाद, न्यायिक अभिरक्षा में होने के कारण,कारागृह प्रशासन द्वारा आई.जी.आई.एम.एस. अस्पताल में भर्ती कराया।

(v) उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी बहन रमा देवी (अ.सा. -24) ने पूर्व में लोकसभा चुनाव लड़ा था। बृज बिहारी प्रसाद की मृत्यु के बाद रमा देवी (अ.सा. -24) ने विधानसभा चुनाव लड़ा।

(vi) उनका कहना है कि उन्होंने रमा देवी (अ.सा. -24) के चुनाव अभियान में भी भाग लिया था।

(vii) उन्होंने इस तथ्य को जानने से इनकार किया कि मोतिहारी निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों में से एक देवेंद्र नाथ दुबे, रमा देवी (अ.सा. -24) के मुख्य प्रतिद्वंद्वी थे।

(viii) उन्होंने आगे इस बात से भी इनकार किया कि बृज बिहारी प्रसाद ने अपने भाई श्याम बिहारी प्रसाद के साथ मिलकर देवेंद्र नाथ दुबे की हत्या की थी।

(ix) उन्होंने घटना स्थल पर अपनी उपस्थिति की पुष्टि की और दावे को इनकार कर दिया कि वह घटना का गवाह नहीं था।

(x) उन्होंने इस सुझाव का खंडन किया कि बृज बिहारी प्रसाद के बहनोई होने के नाते, वे झूठे साक्ष्य दे रहे हैं।

(xi) उन्होंने इस दावे का भी खंडन किया कि वह अपनी बहन रमा देवी (अ.सा. -24) के इशारे पर गवाही दे रहे थे।

(xii) वह दोहराते हैं कि महंथ अश्वनी दास (अ.सा. -25) और अन्य अस्पताल में उपस्थित थे।

(xiii) दो प्रहरी, जिनमें लक्ष्मेश्वर साहू भी शामिल थे, बृज बिहारी प्रसाद के बगल में चल रहे थे।

(xiv) गोलीबारी के बाद अस्पताल के कर्मचारी और अन्य उपस्थित लोग अलग-अलग दिशाओं में दौड़ना आरंभ कर दिया।

(xv) रमा देवी (अ.सा. -24) घटना के बाद अस्पताल आई। वह बृज बिहारी प्रसाद के शव के पास उसे रोते हुए देखने की गवाही देता है।

(xvi) पुलिस अधिकारियों ने बृज बिहारी प्रसाद के शव की जांच की और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया है।

(xvii) वह अगली सुबह 14.06.1998 को अस्पताल गए थे।

(xviii) उन्होंने उल्लेख किया कि उनका पुलिस बयान घटना के लगभग 10-12 घंटे[12] बाद दर्ज किया गया था, लेकिन सही तिथि स्मरण नहीं है क्योंकि यह सात वर्ष पहले लिया गया था।

13. हालाँकि यह बताया गया कि पारस नाथ चौधरी (अ. सा. -1) अपनी गवाही में अस्पताल के कमरे का नंबर याद नहीं कर पाए या यह याद नहीं रख पाए कि यह दक्षिण की ओर था या नहीं, लेकिन हमारी राय में यह पहलू उनकी मुख्य गवाही को प्रभावित नहीं करता। यह ध्यान देने योग्य है कि पारस नाथ चौधरी (अ. सा. -1) को पता था कि अस्पताल का कमरा भूतल पर था और पश्चिम की ओर 4-5 कमरों को पार करने के बाद एक बरामदा था। उन्होंने आगे कहा कि वहाँ एक साइकिल स्टैंड, बैठने के लिए एक खाली जगह और एक सड़क थी जो पश्चिम की ओर बेली रोड से जुड़ती है।

14. पारस नाथ चौधरी[13] (अ. सा. -1) स्वीकार करते हैं कि उन्होंने अस्पताल में बृज बिहारी प्रसाद से मिलने के लिए न्यायालय या कारागृह अधिकारियों से पूर्व अनुमति नहीं ली थी, न ही उन्होंने अस्पताल के पंजिका में कोई प्रविष्टि की थी। यह अन्य आगंतुकों के लिए भी सच है, एक स्थिति जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा स्वीकार किया जाता है। पंजिका प्रविष्टि या पूर्व अनुमति की अनुपस्थिति, एक कारक जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए, यह साबित करने वाले प्रचुर और विश्वसनीय साक्ष्य और सामग्री को त्यागने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है कि बृज बिहारी प्रसाद, एक प्रभावशाली राजनीतिक नेता, ने अस्पताल में कई आगंतुकों और समर्थकों से मुलाकात की थी। फर्दबयान (प्रदर्श-50) और रमा देवी[14] (अ.सा.- 24) और महंत अश्विनी दास[15]

12 विचारण न्यायालय अभिलेख, खंड II, पी.58 देखें।

13 अनु 11 (xv) देखें।

14 अनु 23 देखें।

15 अनु 17 (ii) देखें।

(अ.सा.-25) के चक्षु साक्ष्य, पारस नाथ चौधरी (अ.सा.- 1) और अन्य आगंतुकों की उपस्थिति स्थापित करते हैं। इसके अलावा, निम्नलिखित गवाह विवरण आगंतुकों और चशमदीद गवाहों की उपस्थिति को स्थापित करते हैंः

- अमरेंद्र कुमार सिन्हा (अ.सा.- 10) ने गवाही दी और अरविंद सिंह (अ.सा.- 13), शशि भूषण सिंह (अ.सा.- 42), राम निरंजन चौधरी (ए-6) और 7-8 अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति को स्वीकार कर लिया है।
- अरबिंद सिंह (अ.सा.- 13), जिन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया था, ने स्वीकार किया कि अमरेंद्र कुमार सिन्हा (अ.सा.- 10), शशि भूषण सिंह (अ.सा.- 42) और 5-7 अन्य व्यक्ति अस्पताल आए थे।
- रवींद्र भगत (अ.सा.- 14), घायल गवाह, जो पक्षद्रोही हो गया, ने बृज बिहारी प्रसाद के साथ दो अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति की गवाही दी।

एक बार घटना स्थल पर एक गवाह की उपस्थिति सिद्ध हो जाने के बाद, उनकी गवाही, यदि विश्वसनीय और सच्ची है, तो पूरी तरह से अस्पताल और कारागृह नयाचार का पालन न करने के आधार पर खारिज नहीं की जानी चाहिए।

15. उच्च न्यायालय द्वारा पारस नाथ चौधरी (अ.सा.- 1) के प्रत्यक्षदर्शी विवरण की अवहेलना और संदेह करने के लिए दिया गया तर्क, इस आधार पर कि उन्हें सूचनादाता होना चाहिए था क्योंकि वह बृज बिहारी प्रसाद के बहनोई हैं और घटना के समय अस्पताल में मौजूद थे, अनुमानात्मक और निराधार है। यह तथ्य *वास्तव में* उनकी गवाही को अस्वीकार नहीं कर सकता है। इस तरह की धारणा यह निर्धारित करने के लिए एक कठोर सूत्र लागू करती है कि कौन एक सूचनादाता होना चाहिए, जिसकी कानून कल्पना नहीं करता है। यह एक स्वीकृत और मान्य स्थिति है कि पारस नाथ चौधरी (अ.सा.- 1) का नाम अस्पताल में मौजूद व्यक्तियों में से एक के रूप में फर्दबयान और प्राथमिकी में उल्लेख किया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी

मामले का सूचनादाता हो सकता है, और पुलिस भी स्वयं से मामला दर्ज कर सकती है। पारस नाथ चौधरी (अ.सा.- 1) की गवाही को खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय का तर्क मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण है।

16. उनकी गवाही को अस्वीकार करने का एक और कारण अस्पताल में हमलावर के रूप में राजन तिवारी (ए-9) की उपस्थिति के बारे में विरोधाभास है। अपने पुलिस बयान में, पारस नाथ चौधरी (अ.सा. -1) ने राजन तिवारी (ए-9) की पहचान अस्पताल में होने के रूप में की, लेकिन अपने न्यायालय के बयान में, उसने कहा कि राजन तिवारी (ए-9) उपस्थित नहीं था। हमारे विचार में, यह विरोधाभास पारस नाथ चौधरी (अ.सा. -1) के मंटू तिवारी (ए-4) और विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला (ए-8) को अपराध करते हुए देखने के विवरण को कमजोर नहीं करता है। भारतीय विधि इस सिद्धांत को मान्यता नहीं देता है- *फाल्सस इन यूनो, फाल्सस इन ओम्निबस।* **दीप चंद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य**[16], में न्यायालय ने यह कहा था कि मैक्सिम फाल्सस इन यूनो,फाल्सस इन ओम्निबस इस देश की स्थितियों में लागू करने के लिए एक अच्छा नियम नहीं है। यह उक्ति कानून के शासन का दर्जा नहीं रखती है। यह केवल सावधानी का एक नियम है जिसमें साक्ष्य के भार का प्रश्न शामिल है जिसे न्यायालय दी गई परिस्थितियों में लागू कर सकती है।[17] ऐसे मामलों में जहां एक गवाह को अविश्वसनीय साक्ष्य देते हुए पाया जाता है, यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह शेष साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच करे, भूसी से अनाज को अलग करे। विश्वसनीय साक्ष्य पर विशेष रूप से भरोसा किया जा सकता है जब अभियोजन मामले का आधार बरकरार रहता है। न्यायालय को सच और झूठ को अलग करने के लिए सतर्क होना चाहिए। केवल असाधारण परिस्थितियों में, जब सच्च और झूठ

16 (1969) 3 एस सी सी 890

17 पोन्नम चंद्रैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2008) 11 एससीसी 640

इतने अटूट रूप से जुड़े होते हैं कि उन्हें अलग करना असंभव हो जाता है,तो साक्ष्यों के पूरे समूह को ख़ारिज कर दिया जाना चाहिए।

<u>महंत अश्वनी दास की गवाही (अ.सा.- 25)</u>

17. महंत अश्विनी दास (अ. सा. -25) का बयान अभियोजन पक्ष के मामले का समान रूप से समर्थन करता है। उनकी गवाही निम्नलिखित को दर्शाती हैः

(i) 13.06.1998 को, वह लगभग 7:00 बजे पूर्वाह्न में बृज बिहारी प्रसाद से मिलने के लिए आई.जी.एम.एस अस्पताल पहुंचे।

(ii) उन्होंने पारस नाथ चौधरी (अ.सा. -1) की उपस्थिति की पुष्टि की। अमरेंद्र कुमार सिन्हा (अ.सा. -10), अरबिंद सिंह (अ.सा. -13), शशि भूषण सिंह (अ.सा. -42), राम निरंजन चौधरी (ए-6), राम नंदन सिंह (अ.सा. -12), ओंकार सिंह और अस्पताल में कुछ अन्य लोग।

(iii) राम निरंजन चौधरी (ए-6) द्वारा अस्पताल कक्ष में गर्मी होने की टिप्पणी के बाद, बृज बिहारी प्रसाद टहलने के लिए बाहर निकले। बृज बिहारी प्रसाद के साथ राम निरंजन चौधरी (ए-6), लक्ष्मेश्वर साहू और अन्य सुरक्षाकर्मी भी थे।

(iv) इस बीच, एक सूमो कार और एक एंबेसडर कार अस्पताल परिसर के अंदर आई। लगभग 10-12 व्यक्ति उक्त वाहनों से उतरे और बृज बिहारी प्रसाद की ओर बढ़े।

(v) मंटू तिवारी (ए-4) के पास कार्बाइन थी और अन्य के पास पिस्तौल थी।

(vi) उन्होंने विशेष रूप से भूपेंद्र नाथ दुबे (मृतक के रूप में), श्री प्रकाश शुक्ला उर्फ शिव प्रकाश शुक्ला (मृतक के रूप में), राजन तिवारी (ए-9), विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला (ए-8) और सतीश पांडे की पहचान उन व्यक्तियों के रूप में की जो उपरोक्त वाहनों से उतरे थे।

(vii) मंटू तिवारी (ए-4), भूपेंद्र नाथ दुबे (अब मृत) और श्री प्रकाश शुक्ला उर्फ शिव प्रकाश शुक्ला (अब मृत) ने बृज बिहारी प्रसाद पर गोली चलाई। अन्य लोग भी अलग-अलग दिशाओं में अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे थे।

(viii) विजय कुमार शुक्ला @मुन्ना शुक्ला (ए-8), सतीश पांडे और राजन तिवारी (ए-9) ने लक्ष्मेश्वर साहू पर गोली चलाई।

(ix) गोली लगने पर बृज बिहारी प्रसाद और लक्ष्मेश्वर साहू गिर पड़े।

(x) भूपेंद्र नाथ दुबे (अब मृत) ने लक्ष्मेश्वर साहू की कार्बाइन ली और उसके बाद कहा कि काम पूरा हो गया है। उन्होंने "*जय बजरंग बली*" का नारा लगाया।

(xi) उनका हस्ताक्षरित बयान (प्रदर्श-29) भी एक न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा दर्ज किया गया था।

(xii) यह घटना लगभग 8:30 बजे पूर्वाहन में हुई।

(xiii) पुलिस और सी. बी. आई. ने इस संबंध में उनसे पूछताछ की थी।

18. हमने महंत अश्विनी दास (अ.सा. -25) की प्रति-परीक्षण की सावधानीपूर्वक जांच की है। उनकी प्रति-परीक्षा में कहा गया हैः

(i) महंत अश्विनी दास (अ.सा. -25) को 1996 में बृज बिहारी प्रसाद से मिलवाया गया था। यह लगभग उसी समय था जब महंत अश्वनी दास (अ.सा. -25) सनातन धर्म के अनुयायी बने थे।

(ii) वे बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी (अ.सा. -24) को भी 1996 से जानते थे।

(iii) रमा देवी (अ.सा. -24) अदालत में मौजूद थीं जब उनकी गवाही दर्ज की जा रही थी। हालांकि, महंत अश्विनी दास (अ.सा. -25) उससे बात करने से इनकार करते हैं।

(iv) महंत अश्विनी दास (अ.सा. -25) का कहना है कि हालांकि बृज बिहारी प्रसाद से मिलने का कोई विशेष कारण नहीं था, लेकिन वे आम तौर पर पटना में बृज बिहारी प्रसाद से मिलते थे।

(v) इससे पहले भी वह एक अन्य अवसर पर अस्पताल में बृज बिहारी प्रसाद से मिलने गए थे, लेकिन उन्हें इस मुलाकात की तिथि और समय याद नहीं था।

(vi) घटना की तारीख से लगभग 8-10 दिन पहले वे बृज बिहारी प्रसाद से मिले थे।

(vii) उन्हें पता नहीं था कि किस विशिष्ट उपचार के लिए बृज बिहारी प्रसाद को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका कहना है कि चिकित्सा लगभग डेढ़ महीने से चल रहा था।

(viii) वह बृज बिहारी प्रसाद के खिलाफ लंबित किसी भी मामले की जानकारी होने से इनकार करते हैं।

(ix) वह कहते हैं कि वह अपने खिलाफ लंबित किसी भी मामले से अनभिज्ञ है। हालाँकि, उन्होंने स्वीकार किया कि 1979 में उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था, जिसके लिए वह तीन से चार महीने तक कारागृह में रहे थे।

(x) वह कहता है कि उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और 1987 में एक अपील दायर की गई थी; हालाँकि, वह अनिश्चित था कि अपील अभी भी लंबित थी या खारिज कर दी गई थी, और वह अपील किस आधार पर दायर किया गया याद नहीं कर सका।

(xi) उनके पास 13.06.1998 को अस्पताल जाने का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं था।

(xii) उन्होंने मृत्यु सारांश प्रतिवेदन और जब्ती ज्ञापन पर कोई हस्ताक्षर नहीं किए थे।

(xiii) उन्हें नहीं पता था कि ओंकार सिंह (मृतक) की पत्नी ने पुलिस को बयान दिया था कि उनके पति की हत्या बृज बिहारी प्रसाद ने अनुबंध विवाद के कारण की थी।

(xiv) महंत अश्विनी दास (अ.सा. -25) ने गोलीबारी के बाद घटना स्थल पर रहने के बारे में बयान दिया था। उन्होंने पुलिस को आते हुए और बृज बिहारी प्रसाद और लक्ष्मेश्वर साहू के मृत शारीर को उठाते हुए देखा। वह 9:30 बजे पूर्वाहन में बृज बिहारी प्रसाद के आवास के लिए अस्पताल से निकले जहां कामाख्या नारायण सिंह (अ.सा. -15), शिवाजी प्रसाद, राम नंदन सिंह (अ.सा. -12), ओंकार सिंह और राज बाला वर्मा (समाहर्ता, पटना) सहित कई लोग पहले ही इकट्ठे हो चुके थे। उस रात बाद में, 14.06.1998 को, लगभग 12:30 बजे अपराहन वह मुज़फ़्फ़रपुर मठ के लिए रवाना हुए।

(xv) उन्हें पटना में 04.05.2006 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद, उन्हें बिहार सरकार द्वारा वर्तमान मुकदमे में साक्ष्य देने के लिए संरक्षण दिया गया था। सशस्त्र सुरक्षा प्रहरी, जो आम तौर पर उनके साथ उपस्थित नहीं होते थे, न्यायालय जाने के दौरान उनके साथ जाते थे।

(xvi) वे कहते हैं कि वे लगभग 5:00 बजे अपराह्न में बृज बिहारी प्रसाद के स्मृति भवन पहुँचते थे। रमा देवी (अ.सा. -24), उनके चालक और सुरक्षा प्रहरी स्मृति भवन में रहते हैं।

(xvii) गोलीबारी के दौरान वह अस्पताल के कक्ष से लगभग 30-40 कदम दूर छिपा हुआ था।

(xviii) वह बृज बिहारी प्रसाद के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों के कारण झूठे साक्ष्य देने के सुझाव से इनकार करता है।

19. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय ने महंत अश्विनी दास (अ.सा. -25) द्वारा अभियुक्त की गवाही और मिलीभगत को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि वह खुद एक हत्या के मामले में अभियुक्त है और अपील में दोषी ठहराए जाने के बावजूद फरार हो गया था, जबकि वर्तमान मामले में गवाह के रूप में उससे पूछताछ की जा रही थी। उच्च न्यायालय ने यह भी माना था कि महंत अश्विनी दास (अ.सा. -25) को रमा देवी (अ.सा. -24) और मृतक बृज बिहारी प्रसाद का संरक्षण प्राप्त था।

20. एक गवाह की आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए आवश्यक है कि न्यायालय सावधानी के साथ अपने साक्ष्य से संपर्क करें। विवादास्पद अतीत वाले गवाह की गवाही को अपराध स्थल पर उनकी उपस्थिति सहित मामले के आसपास के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किए बिना असत्य या अविश्वसनीय के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। प्रतिद्वंद्वी गिरोहों या समूहों के बीच संघर्ष से जुड़े मामलों में, दोनों पक्षों के सदस्यों की गवाही स्वीकार्य और प्रासंगिक है। यदि न्यायालय इस तरह की गवाही की सत्यता और सच्चाई के बारे में आश्वस्त है, तो इस पर विचार किया जा सकता है। न्यायालय आम तौर पर यह निर्धारित करने के लिए व्यापक संदर्भ का आकलन करती हैं कि क्या पर्याप्त पुष्टि है, जब तक कि साक्ष्य को अविश्वसनीय मानने का कोई वैध कारण नहीं है। महत्वपूर्ण परीक्षा यह है कि क्या गवाह वास्तव में एक चश्मदीद गवाह है और क्या उनकी गवाही विश्वसनीय है। यदि घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति संदेह से परे स्थापित हो जाती है, तो घटना के बारे में उनके विवरण पर

भरोसा किया जा सकता है। इस तरह के साक्ष्य को केवल आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है।[18]

<u>अमरेंद्र कुमार सिन्हा के परिसाक्ष्य (अ. सा. -10)</u>

21. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमरेंद्र कुमार सिन्हा (अ.सा. -10) पक्षद्रोही हो गए, लेकिन उनका मुख्य बयान निम्नलिखित को दर्शाता हैः

(i) वह स्वीकार करता है कि उसने लगभग 9 बजे पूर्वाह्न में 13.06.1998 को फर्दबयान (प्रदर्श -50) रिकॉर्ड किया था। इसमें उनके हस्ताक्षर हैं जो प्रदर्श 12 और 12/1 के रूप में चिह्नित हैं।

(ii) वह लगभग 6:00-6:30 बजे पूर्वाह्न में अस्पताल गए थे उनके साथ अरबिंद सिंह (अ. सा. -13), शशि भूषण सिंह (अ.सा. -42) और 7 से 8 अन्य लोग थे, जिनके बारे में उन्हें याद नहीं है,शामिल थे।

(iii) वे लगभग 6:30 बजे पूर्वाह्न में बृज बिहारी प्रसाद से वार्ड में मिले। उनका कहना है कि यह घटना लगभग 8:15 बजे पूर्वाह्न को हुई और वह, अन्य लोगों के साथ, घटना के बाद तक वहाँ रहे।

(iv) घटना के समय, अमरेंद्र कुमार सिन्हा (अ.सा. -10), अरबिंद सिंह (अ.सा. -13), शशि भूषण सिंह (अ.सा. -42), राम निरंजन चौधरी (ए-6) और कुछ अन्य लोग बृज बिहारी प्रसाद के साथ टहलने के लिए बाहर आए थे।

(v) दो वाहन, एक सूमो और एक अम्बेसडर कार, अंदर आए थे। 5-6 लोग दोनों वाहनों से उतरे और बृज बिहारी प्रसाद की ओर बढ़े। इसके बाद, हमलावरों में से एक ने बृज बिहारी प्रसाद की ओर इशारा किया और उनकी पहचान मंत्री के रूप में की। इसके बाद हमलावरों ने गोलीबारी शुरू कर दी। बृज बिहारी प्रसाद और लक्ष्मेश्वर साहू को गोली मार दी गई और वे गिर गए। अमरेंद्र कुमार

18 यू. पी. राज्य बनाम फरीद खान और अन्य (2005) 9 एस. सी. सी. 103 देखें

सिन्हा (अ.सा. -10) और अन्य लोग पार्किंग की ओर भागे। अभियुक्तों में से एक ने लक्ष्मेश्वर साहू की कार्बाइन ले ली। अस्पताल से बाहर निकलते समय हमलावरों ने '*जय बजरंग बली*' के नारे लगाए। वे पूर्वी द्वार से उन्हीं वाहनों से बाहर निकले।

(vi) उसे वाहनों का पंजीकरण संख्या याद नहीं है। उन्होंने वहां मौजूद अन्य आगंतुकों के साथ अस्पताल के कर्मचारियों को सूचित किया था, जिन्होंने बदले में पुलिस को सूचित किया।

(vii) उन्होंने भूपेंद्र नाथ दुबे (मृतक के रूप में) और मंटू तिवारी (ए-4) की पहचान की। वह अन्य अभियुक्तों की पहचान नहीं कर सका। उन्होंने दावा किया कि भूपेंद्र नाथ दुबे (अब मृत) और मंटू तिवारी (ए-4) के पास पिस्तौल थी।

(viii) जब अमरेंद्र कुमार सिन्हा (अ.सा. -10) से पूछताछ की जा रही थी, तब मंटू तिवारी (ए-4) न्यायालय में उपस्थित नहीं थे। हालांकि, उसने न्यायालय में उपस्थित राम निरंजन चौधरी (ए-6) की पहचान की।

(ix) चूंकि वह अन्य अभियुक्त को नहीं पहचानता था, इसलिए उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया और अभियोजन पक्ष द्वारा उससे प्रति-परीक्षण करने की अनुमति दी गई।

(x) अपने प्रति-परीक्षण में, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि मंटू तिवारी (ए-4) ने अपनी स्टेन गन से गोली चलाई थी।

(xi) उन्होंने पारस नाथ चौधरी (अ.सा. -1) की उपस्थिति से भी इनकार करते हुए दावा किया कि उन्होंने उन्हें अस्पताल में नहीं देखा था।

(xii) हालांकि, वह प्रति-परीक्षण में स्वीकार करता है कि उसने फर्दबयान पर अपने हस्ताक्षर किए थे।

(xiii) बचाव पक्ष द्वारा उनसे विस्तार से प्रति-परीक्षण नहीं किया गया।

22. हम पहले हीं *फाल्सस इन यूनो, फाल्सस इन ओम्निबस* के सिद्धांत की जाँच करते समय इस न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख कर चुके हैं। यही सिद्धांत समान रूप से तब भी लागू होता है जब न्यायालय एक गवाह के बयान की जांच करती है जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। निर्णयों के एक समूह में, इस न्यायालय ने कहा है कि पक्षद्रोही गवाह के साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जाना चाहिए, ताकि अभियोजन पक्ष का समर्थन करने वाले संस्करणों को बाहर रखा जा सके। बल्कि, पक्षद्रोही गवाह की गवाही की गहन जांच की जानी चाहिए, इस प्रकार न्यायालय को सच्चाई को झूठ, अतिशयोक्ति और सुधार से अलग करने में सक्षम बनाना चाहिए। केवल विश्वसनीय साक्ष्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। न्यायालय को उचित मूल्यांकन करने की अपनी शक्ति से वंचित नहीं किया जाता है। पक्षद्रोही गवाह की पूरी गवाही को केवल तभी खारिज किया जाता है जब न्यायाधीश, विवेक के आधार पर, गवाह को पूरी तरह से अविश्वसनीय पाता है, जो साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज करने का आदेश देता है।[19] साक्ष्य के विश्वसनीय भागों पर मामले में साक्ष्य के उद्देश्य से विचार किया जाना चाहिए। यह इस संदर्भ में है कि हमें शिकायतकर्ता/सूचनादाता अमरेंद्र कुमार सिन्हा (अ.सा. -10) की गवाही की जांच करनी है, जिन्होंने फर्दबयान (प्रदर्श पी-50) दिया था, जिसके आधार पर प्राथमिकी (प्रदर्श पी- 50/51) दर्ज की गई थी।

<u>रमा देवी का परिसाक्ष्य (अ. सा. -24)</u>

23. रमा देवी (अ.सा. -24) ने गवाहों-पारस नाथ चौधरी (अ.सा. -1), महंत अश्विनी दास (अ.सा. -25) और अमरेंद्र कुमार सिन्हा (अ.सा. -10) की आइ.जी.आइ.एम.एस अस्पताल में उपस्थिति की पुष्टि की। 13.06.1998 को, रमा देवी (अ.सा. -24) लगभग 2:30 बजे अस्पताल में खाना ले गई थीं और शाम को 7 बजे तक वहाँ रहीं।

19 सी. मुनियप्पन और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य (2010) 9 एससीसी 567 देखें

शाम को अस्पताल से वह अपने बेटों के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए मौर्य लोक गईं और लगभग डेढ़ घंटे तक वहीं रहीं। मौर्य लोक छोड़ते समय, उन्हें अपने पति बृज बिहारी प्रसाद पर हमले के बारे में पता चला। वह तुरंत आई. जी. आई. एम. एस. अस्पताल पहुंची जहाँ उसने बृज बिहारी प्रसाद और लक्ष्मेश्वर साहू को खून से लथपथ मृत पड़ा देखा। कई लोग वहाँ जमा हो गए थे। उन्होंने अस्पताल में पारस नाथ चौधरी (अ.सा. -1), महंत अश्विनी दास (अ.सा. -25) और अमरेंद्र कुमार सिन्हा (अ.सा. -10) की उपस्थिति स्थापित की।

24. हम दो वाहनों में आने वाले व्यक्तियों के बारे में रमा देवी (अ.सा. -24) की गवाही और पारस नाथ चौधरी (अ.सा. -1), महंत अश्विनी दास (अ.सा. -25) और अमरेंद्र कुमार सिन्हा (अ.सा. -10) सहित वहां मौजूद लोगों से सुनी गई घटना के बारे में विस्तृत विवरण को बाहर कर देंगे, जो कि अफवाह है। हालाँकि, पारस नाथ चौधरी (अ.सा. -1), महंत अश्विनी दास (अ.सा. -25) और अमरेंद्र कुमार सिन्हा (अ.सा. -10) की उपस्थिति स्थापित करने वाली उनकी गवाही प्रत्यक्ष साक्ष्य है और इसे खारिज नहीं किया जा सकता है। रमा देवी (अ.सा. -24) घटना से पहले और बाद में काफी समय तक अस्पताल में थीं। उनका संस्करण तथ्यात्मक रूप से सटीक है और आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। इस प्रकार, रमा देवी (अ.सा. -24) की गवाही का उपयोग पारस नाथ चौधरी (अ.सा. -1), महंत अश्विनी दास (अ.सा. -25) और अमरेंद्र कुमार सिन्हा (अ.सा. -10) की गवाही की आंशिक रूप से संपुष्टि और पुष्टिकरण करने के लिए किया जा सकता है।

25. रमा देवी (अ.सा. -24) की गवाही उद्देश्य के दृष्टिकोण से भी प्रासंगिक है, एक ऐसा प्रश्न जो विवादास्पद नहीं है, जैसा कि उनकी प्रति-परीक्षण में उनसे पूछे गए प्रश्नों से स्पष्ट है। उन्होंने हत्या किए गए देवेंद्र नाथ दुबे के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने की पुष्टि की है। उनके पति बृज बिहारी प्रसाद को उक्त मामले में एक आरोपी के रूप में

फंसाया गया था। उनके पति को भी मेधा घोटाले में सी. बी. आई. ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें बेउर कारागृह में रखा गया था। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां से उन्हें आई.जी.आई.एम.एस. अस्पताल के पास भेज दिया गया।

26. मंटू तिवारी (ए-4) स्वर्गीय भूपेंद्र नाथ दुबे (मृतक) का भतीजा है, जो रमा देवी (अ.सा. -24) के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी देवेंद्र नाथ दुबे का भाई था। मोतिहारी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पुनः मतदान से एक दिन पहले देवेंद्र नाथ दुबे की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में बृज बिहारी प्रसाद को आरोपी बनाया गया था। लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी इस तथ्य से और उजागर होती है कि विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला (ए-8) छोटन शुक्ला और भूटकुन शुक्ला का भाई है, जिन्हें कथित तौर पर बृज बिहारी प्रसाद के गुर्गों द्वारा मार दिया गया था। इसके अलावा, रमा देवी (अ.सा. -24) ने गवाही दी कि 1987 में, उनके पति बृज बिहारी प्रसाद पर हत्या का प्रयास किया गया था, जो कथित तौर पर रघुनाथ पांडे (वर्तमान मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया था लेकिन अब उनकी मृत्यु हो चुकी है) के कहने पर किया गया था, जिसमें विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला (ए-8), छोटन शुक्ला और भूटकुन शुक्ला हमले में शामिल थे।

<u>वाहनों और हथियारों की पहचान और गैर-बरामदगी</u>

27. पारस नाथ चौधरी (अ.सा. -1) और महंत अश्विनी दास (अ.सा. -25) ने 13.06.1998 को अभियुक्त द्वारा उपयोग किए गए वाहनों की पहचान की है। उन्होंने विशेष रूप से सुमो पंजीकरण संख्या बीआर-1पी-1818 के बारे में बयान दिया है। सुमो और एम्बेसडर की कारें, जिनका उन्होंने अपने बयानों में उल्लेख किया है, बरामद नहीं की गईं। मृतक लक्ष्मेश्वर साहू से संबंधित कार्बाइन सहित अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद नहीं किए जा सके। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों

को देखते हुए, वाहनों और हथियारों को बरामद करने में पुलिस की विफलता प्रत्यक्षदर्शियों के विवरणों की विश्वसनीयता या बृज बिहारी प्रसाद और लक्ष्मेश्वर साहू की हत्या के कारण के बारे में पुष्टि करने वाले साक्ष्य को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं है। गवाहों के मौखिक बयान की केवल इसलिए अवहेलना नहीं की जानी चाहिए क्योंकि अपराध में इस्तेमाल किया गया हथियार और आरोपी द्वारा कथित रूप से इस्तेमाल किए गए वाहन पुलिस द्वारा पुनर्प्राप्त या जब्त नहीं किए गए थे।[20]

28. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वाहन सं बीआर-1पी-1818 (सुमो), दूसरे आईओ, शशि भूषण शर्मा (अ.सा. -54) के बयान के अनुसार, एक वित्त कंपनी-एसबीआर प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता से भूपेंद्र नाथ दुबे (मृतक) के भाई स्वर्गीय देवेंद्र नाथ दुबे द्वारा एक किराया-क्रय समझौते के तहत लिया गया था। शशि भूषण शर्मा (अ.सा. -54) के प्रति-परीक्षण में उक्त दावे को चुनौती नहीं दी गई थी। वाहन सं. बीआर-1पी-1818 का उल्लेख अमरेंद्र कुमार सिन्हा (अ.सा. -10) के फर्दबयान (प्रदर्श पी-50) में भी किया गया है।

<u>प्रथमिकी का अग्रसारण</u>

29. आक्षेपित निर्णय में कहा गया है कि प्रथमिकी (प्रदर्श 51 और 51/1) पूर्व-समयबद्ध कर दर्ज की गई है। उच्च न्यायालय ने अपने तर्क में इसे अभियुक्त को दोषमुक्त करने के आधारों में से एक के रूप में रेखांकित किया है। वर्तमान मामले में, पहले आई. ओ., एस. एस. पी. यादव की गवाही देने से पहले ही मृत्यु हो गई। हालाँकि, प्रथम सुचना प्रतिवेदन दर्ज करने में कोई संदेह और बहस नहीं है और अमरेंद्र कुमार सिन्हा (अ.सा. -10) द्वारा बयान दिया गया है। हमारे पास चश्मदीद गवाहों के बयान के संबंध में साक्ष्य हैं जो घटना की रात को धारा 161 दं. प्र. सं. के तहत दर्ज किए गए थे,जैसा कि पारस नाथ चौधरी (अ.सा. -1), महंथ अश्विनी दास (अ.सा. -25) और

20 <u>योगेश सिंह बनाम महाबीर सिंह और अन्य</u> (2017) 11 एससीसी 195 देखें जिसमें कई अन्य निर्णयों का उल्लेख है। <u>राजस्थान राज्य बनाम अर्जुन सिंह और अन्य</u> (2011) 9 एससीसी 115 भी देखें

अमरेंद्र कुमार सिन्हा (अ.सा. -10) के बयानों से स्पष्ट है। बृज बिहारी प्रसाद और लक्ष्मेश्वर साहू (प्रदर्श 42/1 और 52) की जांच रिपोर्ट उसी रात तैयार की गई और उसके बाद, डॉ. अरविंद कुमार सिंह (अ.सा. -7) द्वारा क्रमशः 14.06.1998 को सुबह 12:30 बजे और 1:30 बजे पोस्टमार्टम किया गया।

30. यह घटना रात्रि में 13.06.1998 को हुई है, आम तौर पर एफ़ आई आर क्षेत्राधिकार वाले दंडाधिकारी को 14.06.1998 को भेजी जानी चाहिए थी। हालाँकि, 14.06.1998 रविवार होने के कारण अवकाश था। प्रथम सुचना प्रतिवेदन को क्षेत्राधिकार वाले दंडाधिकारी को 15.06.1998 पर भेजा गया था। इसलिए, दं. प्र. सं. की धारा 157 के संदर्भ में क्षेत्राधिकार वाले दंडाधिकारी को प्रथम सुचना प्रतिवेदन की एक प्रति अग्रेषित करने में विलंब के लिए एक स्पष्टीकरण है। यह स्थापित विधि है कि क्षेत्राधिकार वाले दंडाधिकारी को प्राथमिकी भेजने में विलंब अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं है। **राजस्थान राज्य बनाम दाऊद खान**[21]**,** के मामले में इस न्यायालय ने इस विषय पर कानून की जांच की है और कहा है कि जब क्षेत्राधिकार वाले दंडाधिकारी को प्राथमिकी अग्रेषित करने में विलंब होती है और अभियुक्त उसी के बारे में एक विशिष्ट विवाद उठाता है, तो उन्हें यह प्रदर्शित करना चाहिए कि इस विलंब ने उनके मामले को कैसे प्रभावित किया है। केवल विलंब ही अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने और उस पर विश्वास न करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि जांच सही तरीके से शुरू होती है और यह दिखाने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री है कि अभियुक्तों का नाम लिया गया था और उन्हें इंगित किया गया था, तो अभियोजन पक्ष के मामले को तब स्वीकार किया जा सकता है जब साक्ष्य अभियुक्त को शामिल करते हैं। प्रथम सुचना प्रतिवेदन की एक प्रति क्षेत्राधिकार वाले दंडाधिकारी को भेजने और देने की आवश्यकता प्रथम सुचना प्रतिवेदन की पूर्व तिथि या पूर्व समयबद्ध के

21 (2016) 2 एस.सी.सी 607

खिलाफ एक बाह्य नियंत्रण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रथम सुचना प्रतिवेदन में कोई हेरफेर या हस्तक्षेप नहीं है। यदि न्यायालय गवाहों को सच्चा और विश्वसनीय पाती है, तो विलंब के लिए ठोस स्पष्टीकरण की कमी को हानिकारक नहीं माना जा सकता है।

<u>प्रत्यक्षदर्शी के पुलिस बयान</u>

31. उच्च न्यायालय, अपने तर्क में, महंत अश्विनी दास (अ.सा. -25) की धारा 161 दं.प्र.सं. के तहत बयान दर्ज करने के स्थान और समय के बारे में मामूली विसंगतियों पर एक अपवाद लेता है। इसी तरह, आक्षेपित निर्णय में शशि भूषण सिंह (अ.सा. -42) और महंत अश्विनी दास (अ.सा. -25) द्वारा दिए गए बयानों पर प्रतिकूल टिप्पणी की गई है कि कौन पहले समय पर अस्पताल पहुंचा था। घटना की तिथि और न्यायालय की गवाही दर्ज करने के बीच 4 से 6 वर्षों से अधिक के समय के प्रवाह को ध्यान में रखते हुए, ये मुद्दे सबसे अधिक सतही और परिधीय हैं और अभियोजन पक्ष के मामले की अवहेलना करने का औचित्य नही रखते हैं। गवाहों से पूछे गए प्रश्न उनकी मूल गवाही की सच्चाई और विश्वसनीयता का परीक्षण करने के लिए पूछे गए प्रश्नों के बजाय स्मृति परीक्षण की प्रकृति में अधिक थे। समान रूप से, सी.बी.आई. के आई.ओ. राय सिंह खत्री (अ.सा. -62) को रमा देवी (अ.सा. -24) की धारा 161 दं.प्र.सं. के तहत दिए गए बयान पर उच्च न्यायालय की टिप्पणी अप्रासंगिक है। रमा देवी के दं.प्र.सं. की धारा 161 के बयान, जिसमें उन्होंने अस्पताल में उपस्थित व्यक्तियों के नाम और विवरण दिए थे, को केवल इस आधार पर दरकिनार नहीं किया जा सकता है। दं.प्र.सं. की धारा 161 के तहत दिए गए बयान स्वयं न्यायालय में साक्ष्य नहीं हैं। धारा 161 दं.प्र.सं. के तहत रमा देवी का बयान 13.06.1998 को दर्ज किया गया था और इसे आरोप पत्र के साथ दायर किया गया था। उक्त बयान के संबंध में उनसे प्रति-परीक्षण नहीं किया गया था।

32. यह दावा कि रमा देवी (अ.सा. -24) का आई.ओ. (अ.सा. -54) शशि भूषण शर्मा को दिया गया दं.प्र.सं. की धारा 161 का बयान अभिलेख में शामिल नहीं किया गया है, पूरी तरह से 13.06.1998 को की गई प्रति-परीक्षण पर आधारित है। रमा देवी (अ.सा. -24) की प्रति-परीक्षा के दौरान की गई स्वीकारोक्ति से स्पष्ट रूप से याददाश्त में कमी झलकती है, जो संभवतः लगभग आठ साल के अंतराल और उनसे की गई लंबी पूछताछ के कारण है। यह एक अच्छी तरह से स्थापित तथ्य है कि एसएसपी यादव 13.06.1998 को आईओ थे, जिससे शशि भूषण शर्मा (अ.सा. -54) के लिए उस तारीख को उसका धारा 161 दं.प्र.सं. बयान दर्ज करना असंभव हो गया था। इसके अलावा, शशि भूषण शर्मा (अ.सा. -54) से कभी इस बारे में प्रश्न नहीं किया गया कि क्या उन्होंने 13.06.1998 को रमा देवी (अ.सा. -24) की धारा 161 दं.प्र.सं. का बयान दर्ज किया था। वास्तव में, बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष दोनों इस बात से सहमत हैं कि शशि भूषण शर्मा (अ.सा. -54) ने 14.07.1998 को अन्वेषण संभाला।

<u>गवाहों की पुष्टि एवं जवाबी गोलीबारी</u>

33. यह तर्क कि पारस नाथ चौधरी (अ.सा. -1) और महंत अश्विनी दास (अ.सा. -25) मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन, फर्दबयान, प्रथमिकी आदि के गवाहों को प्रमाणित नहीं कर रहे थे, अप्रासंगिक है और किसी भी तरह से उनके चक्षु-साक्ष्य को कमजोर नहीं करता है। इसी तरह, यह तर्क कि जवाबी गोलीबारी के दौरान वे घायल नहीं हुए थे, निरर्थक है क्योंकि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि हमले का निशाना बृज बिहारी प्रसाद थे। सशस्त्र अंगरक्षक जिन पर हमला किया गया था जवाबी कार्रवाई की थी। हालांकि यह सच है कि पारस नाथ चौधरी (अ.सा. -1) और महंत अश्विनी दास (अ.सा. -25) के बयानों में अंगरक्षकों द्वारा जवाबी गोलीबारी का उल्लेख नहीं है, जो एक स्वतंत्र रूप से सिद्ध तथ्य है, लेकिन यह अकेले घटनास्थल पर

उनकी उपस्थिति या अपराध करने वाले व्यक्तियों की दोषसिद्धि सहित उनके बयानों को खारिज करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।

भा.दं.सं. की धारा 307 के साथ धारा 34 के अंतर्गत अपराध

34. रवीन्द्र भगत (अ.सा. -14) ने शाम को लगभग 7 से 7:30 बजे पूर्वाह्न में आई. जी. आई. एम. एस. अस्पताल में अपनी उपस्थिति का दावा किया था जब बृज बिहारी प्रसाद पर हमले के दौरान उन्हें गोली चलाई गई और उनके बाएं हाथ में गोली लग गई। उन्होंने अपने भाई संजीव कुमार को फोन किया, जो उन्हें चिकित्सा के लिए आलोक नर्सिंग होम ले गए। रवीन्द्र भगत (अ.सा. -14) ने हालांकि दोषियों की पहचान नहीं की। डॉ. तारकेश्वर प्रसाद सिंह (अ.सा. -8) ने 9:30 बजे पूर्वाह्न में 13.06.1998 को घायल रवींद्र भगत (अ.सा. -14) की जांच की और आघात प्रतिवेदन दिनांक 08.08.1998 (प्रदर्श-10) निर्गत की। डॉ. तारकेश्वर प्रसाद सिंह (अ.सा. -8) का बयान रवींद्र भगत (अ.सा. -14) के चिकित्सकीय जाँच से लगभग कुछ घंटे पहले बाएँ हाँथ में दो गोली लगने से हुए प्रवेश और निकास घावों को संदर्भित करता है। किसी भी मामले में, यह साबित होता है कि लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थित होने के बावजूद, व्यापक गोलीबारी हुई और मारने के इरादे से आग्नेयास्त्रों का उपयोग किया गया। इसलिए भा. दं. सं. की धारा 307 के तहत आरोप स्थापित और सिद्ध होता है।

आपराधिक षड्यंत्र का आरोप

35. इस मामले को अधिसूचना दिनांक 07.03.1999 द्वारा सी. बी. आई. को स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसके अनुसार उसने एक अन्वेषण संचालित किया। सी. बी. आई. ने सूरज भान सिंह (ए-1), राम निरंजन चौधरी (ए-6), शशि कुमार राय (ए-7) और रघुनाथ पांडे को साजिशकर्ताओं के रूप में शामिल करते हुए दो पूरक आरोप पत्र दायर किए, जो घटना के लिए जिम्मेदार थे। शशि कुमार राय (ए-7) के खिलाफ

08.11.2000 को एक पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसके बाद रघुनाथ पांडे के खिलाफ दूसरा पूरक आरोप पत्र दिनांक 20.04.2001 को दायर किया गया था।

36. अभियोजन पक्ष ने बेउर कारागृह में हुए अभिकथित बैठक के आधार पर षड्यंत्र का आरोप लगाता है जो बेउर जेल में हुई थी जहां सूरज भान सिंह (ए-1) को कैद किया गया था। कहा जाता है कि सूरज भान सिंह (ए-1) ने कथित तौर पर विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला (ए-8), ललन सिंह (ए-3) और राम निरंजन चौधरी (ए-6) से मुलाकात की थी। हालाँकि, इस बैठक के गवाह, सोन लाल (अ.सा. -32) और लाल बाबू चौधरी (अ.सा. -39) पक्षद्रोही हो गए और अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन नहीं किया। यह साक्ष्य शशि भूषण शर्मा (अ.सा. -54) की गवाही पर आधारित है कि सोन लाल (अ.सा. -32) और लाल बाबू चौधरी (अ.सा. -39) ने घटना की तिथि के लगभग दो महीने बाद 19.08.1998 को उक्त कारागृह बैठक के बारे में उन्हें सूचित किया था। शशि भूषण शर्मा (अ.सा. -52) यह स्थापित करने में विफल रहे कि उन्होंने सोन लाल (अ.सा. -32) और लाल बाबू चौधरी (अ.सा. -39) के कथित संस्करण का पता कैसे चला। वह यह भी स्थापित करने में असमर्थ था कि जिस कैदी से सोन लाल (अ.सा. -32) और लाल बाबू चौधरी (अ.सा. -39) कथित रूप से मिलने गए थे, वह संजय सिंह घटना से दो-तीन दिन पहले बेउर कारागृह में मौजूद था। सोन लाल (अ.सा. -32) और लाल बाबू चौधरी (अ.सा. -39) के बेउर कारागृह जाने का कोई अभिलेख नहीं है।

37. इसके अलावा, राम निरंजन चौधरी (ए-6) के संदिग्ध चरित्र के बारे में अभियोजन पक्ष का दावा और यह कि उसने बृज बिहारी प्रसाद को अपने अस्पताल कक्ष से बाहर टहलने के लिए प्रोत्साहित किया, प्रत्यक्ष रूप से निहितार्थ पूर्ण नहीं है। बल्कि, यह एक ऐसी धारणा है जिसे स्थापित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य की आवश्यकता होती

है। यह केवल राम निरंजन चौधरी (ए-6) के बारे में संदेह व्यक्त करता है, जो एक अंदरूनी सूत्र था जो जानकारी दे सकता था।

38. षड्यंत्र के आरोप को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने मोकामा लैंडलाइन संख्या 32772 के दूरभाष अभिलेख पर भरोसा किया, जिसे कथित तौर पर सूरज भान सिंह (ए-1) द्वारा अभिदान किया गया था। दूरभाष अभिलेख से पता चलता है कि मोकामा लैंडलाइन संख्या 32772 से शशि कुमार राय (ए-7), सुनील सिंह (ए-5) (मृतक) और मुन्ना शुक्ला (ए-8) को कॉल किए गए थे। अभियोजन पक्ष ने भारत संचार निगम लिमिटेड के उप-मंडल अभियंता (सतर्कता) शिया शरण राम (अ. सा. -2) द्वारा प्रस्तुत 29.10.1999 (प्रदर्श-1) के प्रतिवेदन पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि लैंडलाइन टेलीफोन श्रवण कुमार अग्रवाल के नाम से था, लेकिन मोकामा में सूरज भान सिंह (ए-1) के घर में काम कर रहा था। हालांकि, शिया शरण राम (अ. सा. -2) की उक्त प्रतिवेदन एस. एम. एम. रहमान, उप-मंडल अभियंता, बरह और जीतन मेहता, कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी, हाथीदह के भौतिक सत्यापन पर आधारित है, दोनों की जांच नहीं की गई है। इसके अलावा, श्रवण कुमार अग्रवाल की भी जांच नहीं की गई है। एस. एम. एम. रहमान और जीतन मेहता द्वारा तैयार की गई मूल प्रतिवेदन भी अभिलेख में नहीं है। लैंडलाइन टेलीफोन को सूरज भान सिंह (ए-1) से संबंधित सिद्ध करने वाला अभियोजन पक्ष का बयान एम. एल. मीणा (अ.सा. -60), सहायक आई. ओ., सी. बी. आई. की गवाही पर निर्भर करता है। हालाँकि, एम. एल. मीना (अ.सा. -60) अपनी गवाही में स्वीकार करते हैं कि वह किसी दूरभाष सेट के अस्तित्व को सत्यापित करने के लिए घर में प्रवेश नहीं किया बल्कि, उनका पूरा संस्करण सूरज भान सिंह (ए-1) की सौतेली माँ के साथ उनकी बातचीत पर आधारित है। राय सिंह खत्री (अ.सा. -62) द्वारा बयान के अनुसार, 11.05.1998 और 11.06.1998 के बीच कॉल के आदान-प्रदान का संकेत देने वाले

दूरभाष अभिलेख,प्रकट करने वाली और भारी आपत्तिजनक सामग्री के अभाव में षड्यंत्र के आरोप को पर्याप्त रूप से सिद्ध और स्थापित नहीं करते हैं।

39. सी.बी.आई. ने विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला (ए-8) के कहने पर 15.06.1998 को गाँव खानजाह घाट में आयोजित घटना के बाद के उत्सव पर भी भरोसा किया। आमोद कुमार (अ.सा. -11), सुशील कुमार सिंह (अ.सा. -35) और पूजा (अ.सा. -37), जो घटना के बाद के उत्सव के कथित गवाह थे,पक्षद्रोही हो गए। अवधेश कुमार सिंह (अ.सा. -36) का बयान, जो पक्षद्रोही नहीं हुआ, घटना की तिथि के एक साल और दो महीने बाद दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष ने यह दिखाने के लिए कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं रखी है कि कैसे एम.एल. मीणा, आई. ओ., सी. बी. आई. (अ.सा. -60) ने अवधेश कुमार सिंह (अ.सा. -36) का पता लगाया था, हालांकि राय सिंह खत्री, आई. ओ., सी. बी. आई. (अ.सा. -62) ने कहा था कि एम. एल. मीणा, आई. ओ., सी. बी. आई. (अ.सा. -60) अवधेश कुमार सिंह (अ.सा. -36) के संपर्क में थे। अवधेश कुमार सिंह (अ.सा. -36) और पूजा (अ.सा. -37) द्वारा घटना के बाद के उत्सव में शशि कुमार राय (ए-7) की उपस्थिति स्थापित करने का साक्ष्य पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है। किसी भी मामले में, शशि कुमार राय (ए-7) का वर्तमान अपीलों के लंबित रहने के दौरान निधन हो गया।

40. षड्यंत्र के आरोप को मजबूत करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने बृज बिहारी प्रसाद की जान को खतरे के संबंध में फैक्स संदेश (प्रदर्श-6) पर भरोसा किया है। इस फैक्स संदेश से अभियोजन पक्ष को अभियुक्त व्यक्तियों-सूरज भान सिंह (ए-1), मुकेश सिंह (ए-2), ललन सिंह (ए-3) और कैप्टन सुनील सिंह (ए-5) (अब मृत) को आपराधिक षड्यंत्र के आरोप में फंसाने में मदद नहीं मिलेगी।

<u>राजन तिवारी (ए-9) की उपस्थिति के संदर्भ में विसंगति</u>

41. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पारस नाथ चौधरी (अ. सा. -1) ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा था कि राजन तिवारी (ए-9) बृज बिहारी प्रसाद और लक्ष्मेश्वर साहू की हत्या करने वाले अन्य अभियुक्तों के साथ मौजूद नहीं था। भले ही महंत अश्विनी दास (अ.सा. -25) ने राजन तिवारी (ए-9) की उपस्थिति का उल्लेख किया था, लेकिन दो प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान में विसंगति को देखते हुए, हमें लगता है कि संदेह का लाभ राजन तिवारी (ए-9) को दिया जाना चाहिए।

<u>निष्कर्ष</u>

42. भले ही हम शशि भूषण सिंह (अ.सा. -42) की गवाही को पूरी तरह से खारिज कर दें, लेकिन पारस नाथ चौधरी (अ.सा. -1), महंत अश्विनी दास (अ.सा. -25) और कुछ हद तक रमा देवी (अ.सा. -24) और अमरेंद्र कुमार सिन्हा (अ.सा. -10) के बयान और अन्य साक्ष्य और तथ्य मंटू तिवारी (ए-4) और विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला (ए-8) के खिलाफ आरोप को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त निर्णायक हैं। भूपेंद्र नाथ दुबे और कैप्टन सुनील सिंह (ए-5) नहीं रहे और इसलिए हमें उनके खिलाफ साक्ष्यों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह, हमें शशि कुमार राय (ए-7) के बयानों की जांच करने की आवश्यकता नहीं है, जिनकी वर्तमान अपीलों के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी।

43. सूरज भान सिंह (ए-1), मुकेश सिंह (ए-2), लल्लन सिंह (ए-3) और राम निरंजन चौधरी (ए-6) के खिलाफ षड्यंत्र के सवाल और साक्ष्य के संबंध में, पारस नाथ चौधरी (अ. सा. -1) और महंत अश्विनी दास (अ.सा. -25) की गवाही के माध्यम से उन्हें फंसाने के लिए कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। चूंकि षड्यंत्र के आरोप की पुष्टि नहीं हुई है, हम उन्हें दोषमुक्त करने वाले उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और वे संदेह के लाभ के हकदार हैं।

44. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम निम्नानुसार मानते हैं और निर्देश देते हैंः

क) मंटू तिवारी (ए-4) और विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला (ए-8) के खिलाफ भा. दं. सं. की धारा 302 के साथ धारा 34 के तहत बृज बिहारी प्रसाद और लक्ष्मेश्वर साहू की हत्या के आरोप साबित हुए हैं और संदेह से परे साबित हुए हैं।

ख) मंटू तिवारी (ए-4) और विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला (ए-8) के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप, जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 34 में कहा गया है, साबित हुए हैं और संदेह से परे साबित हुए हैं।

ग) मंटू तिवारी (ए-4) और विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला (ए-8) को भा.दं.सं. की धारा 302 और 307 के साथ धारा 34 के तहत विचरण न्यायालय द्वारा दी गई सजा और सजा की पुष्टि की जाती है और उसे बहाल किया जाता है।

घ) परिणामस्वरूप, मंटू तिवारी (ए-4) और विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला (ए-8) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत आजीवन कारावास और 20,000/- (बीस हजार रुपये मात्र) प्रत्येक को जुर्माना भरना होगा, तथा इसके अतिरिक्त उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 307 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत पांच वर्ष के कठोर कारावास और 20,000/- (बीस हजार रुपये मात्र) प्रत्येक को जुर्माना भरना होगा। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। दं. प्र. सं. की धारा 428 लागू होगी। चूंकि विचरण न्यायालय द्वारा डिफ़ॉल्ट सजा नहीं लगाई गई थी, इसलिए हम निर्देश देते हैं कि प्रत्येक खाते पर जुर्माना न भरने की स्थिति में मंटू तिवारी (ए-4) और विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला (ए-8) को छह महीने के कठोर कारावास की सजा काटनी होगी।

ड़) मंटू तिवारी (ए-4) और विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला (ए-8) को आज से दो सप्ताह के भीतर संबंधित जेल अधिकारियों/अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है ताकि वे अपनी-अपनी सजा की शेष अवधि काट सकें। आत्मसमर्पण न करने की स्थिति में अधिकारी उन्हें कानून के अनुसार गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने के लिए उचित कदम उठाएंगे।

च) जहां तक सूरजभान सिंह (ए-1), मुकेश सिंह (ए-2), लल्लन सिंह (ए-3), राम निरंजन चौधरी (ए-6) और राजन तिवारी (ए-9) का संबंध है, हम उन्हें संदेह का लाभ देते हैं और उनकी बरी किए जाने को बरकरार रखते हैं।

45. अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और उपरोक्त पैराग्राफ 44 में जारी निर्देशों के अनुसार आक्षेपित निर्णय को रद्द किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा किया जाएगा।

मामले का परिणाम: अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

*लेखक

[1] हेडनोट तैयार किए गए: दिव्या पांडे